



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]
No. 142]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 209(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2005

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3, आदेश 2005 है ।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तंभ (2) से (13) में से प्रत्येक में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां उन स्तंभों में वर्णित सेक्टरों या सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों और “विशेष समस्याओं” के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी की प्रकृति के व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :-

सारणी

निम्नलिखित से संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए

राज्य	जिला प्रशासन	पुलिस प्रशासन	कारागार प्रशासन	अग्नि	न्यायिक	स्वास्थ्य	प्रारंभिक शिक्षा	कंप्यूटर प्रशिक्षण	सार्वजनिक पुस्तकालय	विरासत संरक्षण	पारंपरिक जल स्रोतों की वृद्धि	विशेष समस्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(रुपए लाख में)												
आंध्र प्रदेश	39.70	10.00	510.00	98.90	56.00
अरुणाचल प्रदेश	165.57	135.00	150.00
असम	..	678.51	103.74	50.00	..	1076.04	..	516.73	735.75
बिहार	..	199.71	225.00	436.02	..	1614.06	2017.77	951.10	79.00	139.32	844.77	115.00
छत्तीसगढ़	..	182.25	42.23	100.00	..	121.20	294.66	..	295.80	..	155.66	..
गुजरात	..	834.22	000	388.57	1287.27	356.04	538.02	324.27	60.00	..	1846.02	774.22
हरियाणा	..	819.22	44.56	39.34	..	200.00	234.68	..	0.10	..	50.00	2532.19
हिमाचल प्रदेश	..	559.02	10.00	..	34.00	289.90
कर्नाटक	2684.60	1220.69	179.34	308.07	660.82	403.80	63.70	..	207.20	2287.90
केरल	..	101.55	..	149.34	344.69	90.00	..	150.50	330.18	20.00	64.50	..
मध्य प्रदेश	..	155.10	2469.52	193.50	..	319.06	..	263.51
महाराष्ट्र	..	370.00	..	100.00	483.68	700.00	150.00	200.00	200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मणिपुर	..	52.10	54.78	59.78	..	60.00	59.78	49.78	18.00	449.56
मेघालय	..	133.72	23.16	49.78	..	208.68	49.78	34.78	198.12	..
मिजोरम	423.12	132.31	..	29.67	..	254.63	19.68	171.24	198.90	49.78	74.53	2090.76
नागालैंड	..	21.30	5.00	27.68	10.00	34.40
उड़ीसा	..	219.46	116.50	168.47	..	465.55	870.24	771.56	640.16	647.79
राजस्थान	..	724.75	60.00	872.74	240.70	710.90	697.76	..	74.00	100.00	536.20	238.54
तमिलनाडु	660.00	323.00	80.00	180.70	194.99	184.70	490.00
त्रिपुरा	..	162.55	10.00	102.82	18.00	39.67	64.00	100.00
उत्तर प्रदेश	..	70.13	317.76	2127.00	2235.13	..	145.00	..	1631.50	337.30
उत्तरांचल	118.00	348.27	124.48	137.54	..	538.02	1235.65	321.37	31.01	78.15	303.09	374.82
पश्चिमी बंगाल	266.09	78.94	298.90	627.27	..

परंतु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, ऊपर विनिर्दिष्ट और राज्य स्तरीय सशक्त समितियों द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परंतु यह और कि राज्यों को न दी गई ऐसी रकम और राज्यों को दी गई रकम जो उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए 31 मार्च, 2005 तक उपयोग नहीं की गई है, राजवित्तीय सुधार सुविधा के अंतर्गत प्रोत्साहन निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि से कम है, तो इस प्रकार अधिक संदत्त राशि का किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध, जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संदेय हो सकती है, समायोजन किया जाएगा ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

ए.पी.जे.अब्दुल कलाम,

राष्ट्रपति ।

[फा.सं.19(4)/05-वि.1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 209(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 206”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No.3 ORDER, 2005

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2005.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2004, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (13) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards and “special problems” relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns, namely:—

TABLE
For upgradation of standards relating to

State	District Admini- tration	Police Admini- tration	Jail Admini- tration	Fire	Judicial	Health	Elementary Education	Computer Training	Public Libraries	Heritage Protection	Augmentation of Traditional Water Sources	Special Problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							(Rupees in lakhs)					
Andhra Pradesh			39.70	10.00			510.00	98.90	56.00			
Arunachal Pradesh							16.57				135.00	150.00
Assam		678.51	103.74	50.00		1076.04		516.73				735.75
Bihar		199.73	225.00	436.02		1614.06	2017.77	951.10	79.00	139.32	844.77	115.00
Chhattisgarh		182.25	42.23	100.00		121.20	294.66		295.80		155.66	
Gujarat		834.22		388.57	1287.27	356.04	538.02	324.27	60.00		1846.02	774.22
Haryana		819.22	44.56	79.34		200.00	234.68		0.10		50.00	2532.19
Himachal Pradesh		559.02					10.00		34.00			298.90
Karnataka	2684.60	1220.89	179.34			308.07	660.82	403.80	63.70		207.20	2287.90
Kerala		101.55		149.34	344.69	90.00		150.50	330.18	20.00	64.50	
Madhya Pradesh		155.10					2489.52	193.50		319.06		263.51
Maharashtra		370.00		100.00	483.68	700.00	150.00				200.00	200.00
Manipur		52.10	54.78	59.78		60.00	59.78			49.78	18.00	449.56
Meghalaya		133.72	23.16	49.78		208.68	49.78			34.78	198.12	
Mizoram	423.12	132.31		29.67		254.63	19.62	171.24	-198.90	49.78	74.53	2090.76
Nagaland		21.30	5.00			27.68	10.00	34.40				
Orissa		219.46	116.50	168.47		485.55	870.24	771.16			840.16	647.79
Rajasthan		724.75	80.00	872.74	240.70	710.90	697.76		74.00	100.00	536.20	838.54
Tamil Nadu	660.00	323.00	80.00	180.70			194.99				184.70	490.00
Tripura		162.55					10.00	102.82	18.00	39.67	64.00	100.00
Uttar Pradesh		70.13	317.76			2127.00	2235.13		145.00		1631.50	337.30
Uttaranchal	118.00	348.27	124.48	137.54		536.02	1235.65	321.37	31.01	78.15	303.09	374.82
West Bengal			266.09	78.94						298.90	827.23	

1098 GT/2005-2

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgradation and standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by State Level Empowered Committees:

Provided further that the amount not released to States and amount released to the States but not utilised by them for this purpose by 31st day of March, 2005 will be transferred to Incentive Fund under Fiscal Reforms Facility:

Provided also that if the actual expenditure on such approved programmes relating to any administration as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(4)/05-LI]

T. K. VISWANATHAN, Secy.